

प्रेषक,

संख्या : 06-सू.क. / 18(1) / 2001 7

एन0एस0नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
टिहरी/पौड़ी गढ़वाल।

राजस्व विभाग

विषय: अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद पौड़ी की तहसील श्रीनगर के ग्राम कोटेश्वर एवं डुंगरीपंत एवं जनपद टिहरी की तहसील देवप्रयाग के ग्राम नैथाणा, गौरासाली, मैणों, साको, सुपाणा, गण्डासू, मरगांव व धारी में कुल 30.033 है० भूमि कय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

देहरादून : दिनांक : 19 जनवरी, 2007

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3374/12अ-6(03-04) दिनांक 02 सितम्बर, 2004 एवं पत्र संख्या-3272/8-6(2003-2004) दिनांक 01 जुलाई, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) एवं उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत जनपद पौड़ी की तहसील श्रीनगर के ग्राम कोटेश्वर एवं डुंगरीपंत एवं जनपद टिहरी की तहसील देवप्रयाग के ग्राम नैथाणा, गौरासाली, मैणों, साको, सुपाणा, गण्डासू, मरगांव व धारी में कुल 30.033 है० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी

अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

7- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग जल विद्युत परियोजना हेतु किया जायेगा।

8- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2- तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3- सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

5- श्री संजय श्रीकृष्ण पाठक, सहायक प्रबन्धक, अलकनंदा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, निवासी- 5 चन्द्र लोक कालोनी, राजपुर रोड, देहरादून।

6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)  
अनु सचिव।